

न्यायिक सुधार

न्यायिक सुधार

परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इस वर्ष संपन्न हुई एक संयुक्त बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से न्यायिक सुधारों (वर्षिक जजों की भारी कमी का समाधान) के लिये वेदनापूर्ण आग्रह किया गया।
- यह एक स्थापित तथ्य है कि न्यायापालिका के कार्यों का कुशल संचालन नियमित व सुचारू रूप से होने वाली नयुक्तियों के द्वारा ही हो सकता है, कति स्वीकृति देने में सरकार द्वारा नषिक्रयिता दरिखाने के कारण अनेक नयुक्तियों अटकी पड़ी हैं।

न्यायिक सुधार क्यों?

- न्यायिक नयुक्तियों के लिये एक उत्तरदायी व पारदर्शी व्यवस्था काम नहीं कर रही है। अतः नयुक्तियों व स्थानांतरण के लिये एक पारदर्शी, और विकासोन्मुखी व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता बढ़ गई है।
- न्यायाधीशों को मनोनीत करने के लिये न तो कोई मापदंड निर्धारित किये गए हैं और न ही नयुक्तियों के लिये प्रस्तावित किये गए नामों का किसी मापदंड पर रीतबिद्ध मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रायः कहा जाता है कि न्यायिक तंत्र में भाई-भतीजावाद की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है, जिसके चलते यह अकुशलताओं से गुजर रहा है।
- उच्च व नचिली अदालतों में भी नयुक्ति में देरी होने के कारण न्यायिक अधिकारियों की कमी हो गई है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। इसी कारण, मामलों के लंबित रहने का अनुपात बढ़ता जा रहा है और यह पूरे भारतीय न्यायिक तंत्र को जकड़ चुका है।
- छोटे कार्यकाल और कार्य के भारी दबावों के कारण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कानून को उत्कृष्ट बनाने और आवश्यक परपिक्वता अर्जति करने का अवसर ही नहीं मलि पाता है।
- न्याय अभी भी देश के बहुसंख्यक नागरिकों की पहुँच के बाहर है, क्योंकि वे वकीलों के भारी खर्च वहन नहीं कर पाते हैं और उन्हें व्यवस्था की प्रक्रियात्मक जटिलता से होकर गुजरना पड़ता है।

प्रस्तावित न्यायिक सुधार

- **नयुक्तियाँ:** प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्ति आयोग द्वारा जजों को नयुक्ति करने की कॉलेजियम व्यवस्था (वर्तमान व्यवस्था) के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि, इसे अनेक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, फिर भी यह प्रभावशाली समाधान हो सकता है, जिसके लिये भारत के मुख्य न्यायाधीश व न्यायापालिका के बीच कार्यकारी शक्तों के लिये संतुलन बैठाना होगा।
- **लंबित मामले:** विचाराधीन मामलों के अनुपात में कमी लाने के लिये कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये, कुछ विशेष श्रेणी के मामलों के समाधान के लिये समय-सीमा तय की जानी चाहिये तथा लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये। इससे न केवल विचाराधीन मामलों की संख्या में आनुपातिक कमी आएगी बल्कि न्यायापालिका के मूल्यवान समय की बचत होगी।
- **अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का निर्माण:** अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतभा को आकर्षित करके यह जजों की योग्यता व गुणवत्ता में सुधार करेगा।
- **तकनीक:** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कुशलतापूर्वक उपयोग से न्यायिक डेटाबेस बनाया जा सकता है। इसके द्वारा जजों के अलग-अलग प्रदर्शनों का आकलन किया जा सकेगा तथा एक संस्था के रूप में न्यायालय के समग्र प्रदर्शन का आकलन भी किया जा सकेगा।
- विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह प्रस्तावित किया है कि खंडपीठों के माध्यम से उच्च न्यायालय के कार्यों का वकिंद्रीकरण किया जाए, जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जाए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद अहस्तांतरणीय बनाया जाए और न्यायाधीशों की संख्या वर्ष 1987 के आधार पर 5 गुना बढ़ाई जाए।

आगे का रास्ता

- जजों की नयुक्ति करने में न्यायापालिका व कार्यपालिका के बीच टकराव खत्म होने चाहिये तथा ऐसा स्वीकार्य समाधान निकलना चाहिये जिसमें दोनों संबद्ध पक्षों के मत्तों को सम्मान मलि सके।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेदनापूर्ण आग्रह को एक बड़ी चेतावनी व अवलिंब समाधान की आवश्यकता के रूप में लिया जाना चाहिये तथा न्यायापालिका की कार्यपद्धति के विधि पक्षों में न्यायिक सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिये, जिनमें नयुक्तियों, स्थानांतरण व अवसंरचनात्मक

वक़ास प्रमुख हैं ।

- इसके अतरक़त, नागरक़ों क़ी बढती हुई भागीदारी से इस चर्चा को बल मला है क़न्यायक़ी व़यवस्था का संचालन क़सि तरह क़या जाए, ज़सिसे यह अपनी राह में आने वाली बाधाओं से नपिट सके तथा आम जनता को न्याय दलाने का वास्तवक़ी उपकरण बन सके ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/Judicial-reform>

